Website : www.highwaychannel.in
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार
हाईवे चैनल
वर्ष- 28 अंक- 255 रायपुर, गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

हसदेव अरण्य कोयला खनन प्रकरण में उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

संघर्ष समिति की याचिका खारिज, सामुदायिक वन अधिकारों का उल्लंघन करने का दावा बेबुनियाद

बिलासपुर, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्राम घठबार्रा के निवासियों की दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सामुदायिक वन अधिकार का कोई ठोस दावा साबित नहीं हुआ है। सरगुजा के उदयपुर तहसील के घठबार्रा ग्रामसभा की बैठकों में सामुदायिक अधिकारों को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वर्ष 2008 और 2011 की ग्रामसभा बैठकों में केवल व्यक्तिगत पट्टों और भूमि अधिकारों की चर्चा हुई थी। ऐसे में यह दावा निराधार है कि ग्रामीणों के सामुदायिक वन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने की।

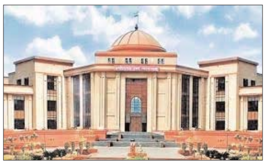

दरअसल, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और जयनंदन सिंह पोर्ते ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि घठबार्रा गांव के लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक अधिकार मिले थे, जिन्हें 2016 में जिला समिति ने रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2022 में फेज-2 कोल ब्लाक खनन की मंजूरी को भी चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि ग्रामसभा की सहमति लिए बिना यह निर्णय अवैध है।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वह ग्रामसभा या गांववालों की ओर से सामुदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती। वहीं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला ने तर्क दिया कि कोल ब्लाक का आवंटन संसद द्वारा पारित कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 2015 के तहत हुआ है। यह अधिनियम अन्य सभी कानूनों पर प्राथमिकता रखता है, इसलिए वन अधिकार कानून की धाराएं इसमें बाधक नहीं है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के वर्ष 2012 और 2022 के आदेशों को सही ठहराया, जिनके तहत पारसा ईस्ट एवं केते बासन (पीईकेबी) कोल ब्लाक के फेज-1 और फेज-2 में खनन की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि खनन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ग्रामसभा की बैठकों और अभिलेखों में सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़ा कोई दावा या प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में जिला समिति द्वारा 2016 में सामुदायिक अधिकारों को रद्द करने का आदेश उचित है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सामुदायिक अधिकारों का कोई वैधानिक दावा सिद्ध नहीं हुआ और न ही याचिकाकर्ता ग्रामसभा की ओर से अधिकृत थे। अदालत ने खनन परियोजना को वैध बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार के आदेशों को बरकरार रखा है।

65 लाख का धान गबन धान खरीदी प्रभारी गिरफ्तार

मुंगेली, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजना धान खरीदी में घोटाले की एक बड़ी खबर मुंगेली जिले से सामने आई है। तरवरपुर धान खरीदी केंद्र में 65 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सरकारी धान के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी सरजू बघेल, खरीदी केंद्र तरवरपुर में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। जांच में सामने आया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान उसने 2094.64 क्विंटल धान का कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया। यह धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 65,02,684 रुपये कीमती था, जो रिकॉर्ड में दर्ज तो था, लेकिन भौतिक रूप से कहीं उपलब्ध नहीं पाया गया। तरवरपुर केंद्र की अनियमितता की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सेतगंगा शाखा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक सुमरन दास मानिकपुरी ने फास्टरपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी इस आधार पर थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 65/2025 दर्ज कर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) एवं 316(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में तत्काल कार्रवाई की गई।

पुलिस ने ग्राम फंदवानीकापा स्थित आरोपी के घर दबिश दी। सरजू बघेल ने पुलिस को देख मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने गबन की बात कबूल की। उसके पास से धान खरीदी रजिस्टर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास द्वारा की कराई गई जांच में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में कुल 39767.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इसमें से 36404.36 क्विंटल धान का परिदान किया गया, जबकि 2094.64 क्विंटल धान गायब पाया गया, जिसकी भरपाई या जवाबदेही नहीं दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह भी सामने आया कि ऑनलाइन सिस्टम में धान दिखाया गया, लेकिन भौतिक सत्यापन में वह मौजूद नहीं था। यह घोर अनियमितता और अमानत में खयानत का मामला बना। इस कार्रवाई से जिला प्रशासन और पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर शुरू हुई यह कार्रवाई अब जिले में अन्य खरीदी केंद्रों की जांच के लिए भी आधार बन सकती है।

ब्रेकिंग न्यूज

कोल्ड्रिफ सिरफ से छिंदवाड़ा के और दो मासूमों ने तोड़ा दम

भोपाल, 9 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। कोल्ड्रिफ जहर से बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 22 हो चला है। कफ सिरप से पीड़ित नागपुर में इलाजरत दो और बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में 19, पांढुर्ना में एक और बैतूल में दो बच्चों की मौत हो के बाद अब तक 22 मासूमों ने अपनी जांच गंवा दी है। अभी भी कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं।

छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि पाँच वर्षीय विशाल की बुधवार शाम को और चार वर्षीय मयंक सूर्यवंशी की देर रात पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे छिंदवाड़ा के परासिया कस्बे के रहने वाले थे। जांच में सामने आया है कि कुछ निजी चिकित्सकों, जिनमें डॉ. प्रवीण सोनी का नाम प्रमुख है, ने बच्चों को 'कोल्ड्रिफ सिरप' दी थी। सिरप पीने के कुछ घंटों बाद ही बच्चों की किडनी प्रभावित होने लगी और हालत लगातार बिगड़ती चली गई। मेडिकल जांच में इस सिरप में जहरीले रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जो शरीर में पहुंचकर किडनी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी कारण कई बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई।

विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही प्रत्याशियों को मिल रही हरी झंडी, कांग्रेस भी आगे

नई दिल्ली3, 9 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर बैठकों का दौर जारी है। सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है लेकिन गठबंधन की कुछ पार्टियों ने कई जगह अपने प्रत्याशी भी फाइनल कर दिया है। इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। यह फैसला दिल्ली में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिया गया है। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस मामले में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया कि कई संभावित सीटों पर विमर्श पूरा हो चुका है और आलाकमान ने इस पर अंतिम मुहर भी लगा दी है। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार अपने पुराने विधायकों पर फिर से भरोसा कर रही है और इनमें से 17 विधायकों को दोबारा टिकट देने का फैसला लिया है।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, यूपी और बिहार में पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं।

चुहिया- हां जी, चुनाव भी जीतना है मोदी सरकार को...!

महिला आयोग अध्यक्ष-सदस्य विवाद का मामला राजभवन पहुंचा

रायपुर, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की कार्यप्रणाली को लेकर अन्य सदस्यों ने मोर्चा खोल रखा है। महिला आयोग का विवाद अब राजभवन पहुंच गया है। दो दिन पहले सुनवाई का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर आयोग की वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

नाराज सदस्यों ने राज्यपाल से की शिकायत कहा- संविधान के अनुसार नहीं हो रहा काम

नाराज सदस्यों लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने राज्यपाल डेका से भेंट कर शिकायती पत्र के साथ दस्तावेज सौंपे और राज्यपाल से राज्य शासन से हस्तक्षेप की मांग की। सदस्यों ने राज्यपाल को महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यहां संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राज्यपाल डेका ने सदस्यों की बातें सुनी और राज्य शासन से इस संबंध में जवाब मांगने का भरोसा दिलाया। नाराज सदस्य राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास गए, लेकिन सीएम दूसरे कार्यक्रमों में गए थे, जिसके कारण मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई।

वेतन बढ़ोतरी और सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कोटवार, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कोटवार लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके हित में राज्य शासन द्वारा अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण आज भी कोटवारों की आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। अपनी मांगों को लेकर कोटवार संघ ने रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

राजनांदगांव कोटवार संघ का कहना है सरकार इनकी बात नहीं मान रही है इनको अन्य राज्यों में जैसा वेतन मिलता है वैसा मिलना चाहिए साथ ही अन्य राज्यों में 12000 वेतन मिलता है और हमको 6000 रुपये हमें अन्य राज्य जैसा वेतन दिया जाए इसी मांग को लेकर आज विरोध स्वरूप कलेक्टर कार्यालय से विरोध स्वरूप रैली निकाली गई राम दरबार तक जिसमें जिले भर के लगभग 700 कोटवार संघ शामिल है।

कोटवारों का कहना है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोटवारों के हित में दिनांक 01/10/2023 को जो आदेश पारित किया गया है, उसी अनुरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोटवारों को भी पारिश्रमिक बढ़ोतरी करते हुए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए आज कोटवार संघ जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठा हुआ है। सेवा भूमि के अनुसार ग्राम कोटवारों की श्रेणी अनुरूप लाभ प्रदान करने की मांग की गई है। साथ ही कोटवारों के सेवा मुक्त होने पर 5 लाख रुपये एवं प्रति वर्ष 1 हजार रुपये बिना हड़ताल के दिए जाने की मांग की गई है।

रायपुर में नर्स की हत्या घर में खून से लथपथ मिली लाश

रायपुर, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर में स्टाफ नर्स की हत्या होने से शहर के सनसनी फैल गई है. खून से लथपथ युवती की लाश घर के कमरे में मिली है. मृतका की पहचान प्रियंका दास (23) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है. पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, प्रियंका दास पिछले एक माह से पचपेड़ी नाका स्थित किराए के रूम में रह रही थी. वह एमएमआई अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर काम कर रही थी. प्रियंका दास मूलत: चिरमिरी जिले की रहने वाली है. हत्या की वारदात देर रात्रि होने की आशंका जताई जा रही है. आज सुबह जब प्रियंका की रूम मेट उनसे मिलने उसके कमरे पहुंची तो प्रियंका के हत्या की जानकारी सामने आई. मृतका के शरीर में चाकू के तीन वार पाए गए हैं. टिकरापारा पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है.

आरकेएम पॉवर प्लांट हादसा : मालिक सहित आठ के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला

सक्ती, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। आरकेएम पॉवर प्लांट में मंगलवार शाम को काम हुई ऊंचाई से लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल 6 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बड़ी लापरवाही पर पुलिस ने प्लांट के मालिक सहित प्रबंधन से जुड़े 8 अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1), 289 एवं 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया है. आरकेएम पॉवर प्लांट के बॉयलर की मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों से भरी लिफ्ट टूटकर गिर गई थी. इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं छह मजदूर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं. मामले में मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह प्लांट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज किया है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम गठित की है, जिसमें डभरा एसडीएम 30 दिवस के अंदर पूरे घटना की जांच कर इसके पीछे की असल वजह ओर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कंपनी के ओनर / डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम, डायरेक्टर टीएम सिंगरवेल, प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर, फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव, बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल, सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत, पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि, लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं।

नए जिला अध्यक्ष के लिए रायपुर शहर व ग्रामीण में एक दर्जन से ज्यादा नाम

कार्यकर्ताओं से टोह लेने के बाद पर्वेक्षक सौंपेंगे रिपोर्ट

ऑब्जर्वर आज से रायपुर शहर एव ग्रामीण मे करेंगे चर्चा

रायपुर, 9 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। कांग्रेस में संगठन सृजन अभियांन के तहत रायपुर शहर एव ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारों की लंबी फौज नजर आ रही है लेकिन इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं यह अनुभवी व काफी लंबे समय से संगठन में कार्य कर चूके हैं ऐसे लोगों को एक बर फिर जिम्मेदारी दी जा सकती है।

रायपुर शहर एव ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी में रायसुमारी के लिए आब्जवर्र प्रफुल्ल गड्धे कल रायपुर पहुंच चूके हैं उनके द्वारा आज से रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं बुद्धजीवो एव अन्य लोगों से चर्चा का दौर चलने वाला है उनके द्वारा किनसे चर्चा की जायेगी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है लेकिन इस बर ज्यादातर जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने का प्रयास चल रहा है इस बार किसी की सिफारिश चलती नजर नहीं आ रही है।वहीं दावेदारों में शहर जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रमुख नाम सामने आ रहे है उनमे घनश्याम राजू तिवारी, श्री कुमार मेनन,विनोद तिवारी, गिरीश दूबे, कन्हैया अग्रवाल, मनोज कंदोई, सुमित दास, सतनाम पनाग, दिलीप सिंह चौहान आदि के नाम शामिल है वहीं रायपुर ग्रामीण से प्रवींण साहू, राजेंद्र पप्पू बंजारे, उधो वर्मा, राम गिड़लानी के नाम प्रमुख रूप से सामने आये हैं।

कांग्रेस संगठन चुनाव

आपको बता दे कि इनमें जिन्होने दावेदारी प्रस्तुत की है उनका राजनीतिक अनुभव भी काफी लंबा रहा है घनश्याम राजू तिवारी अभी प्रदेश कांग्रेस कमिटी में प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं जबकी वह ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर युवा कांग्रेस के साथ-साथ नगर निगम एव सामाजिक क्षेत्र में भी भिन्न पदों पर रह चूके हैं उनके द्वारा वीभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई जा चुकी है वह शहर में एक जाना पहचाना चेहरा है वैसे ही विनोद तिवारी, श्री कुमार मेनन साहित अन्य दावेदारों द्वारा भी वीभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई जा चुकी है ऐसे में इनकी डावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है, गिरीश दुबे वर्तमान में शहर जिला अध्यक्ष हैं ऐसे में उनकी दावेदारी स्वाभाविक मानी जा रही है मनोज कंदोई व सुमितदास भी सामाजिक के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं वहीं रायपुर ग्रामीण के लिए भी जो दावेदारों के नाम सामने आये हैं सभी दिग्गज है और उनका भी राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है चाहे वाह प्रवीण साहू हो या फिर उद्यो वर्मा ,राजेंद्र पप्पू बंजारे या राम गिडलानी यह सभी संगठन के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में वीभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चूके हैं और सभी की पकड़ सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी मजबूत मानी जा रही हैं सभी दावेदार कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में मजबूत नजर आ ए रहे हैं ऐसे में आब्जवर्र को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रायपुर शहर एव जिला अध्यक्ष के लिए वैसे भी छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर राजनीति का केंद्र बिंदु रहता है ऐसे में यहां के जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है उसके मुताबिक ही चयन करना होगा जो भलीभांति संगठन को बेहतर तरीके से चला सके और कहीं गुटबाजी न हो युवा ही बनाना है करके यदि किसी नए नवेले को जिम्मेदारी सौंप दी जाति है और वह चलाने में असमर्थ रहता है तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में चुनाव भी हैं और अभी से कांग्रेस को मैदान में उतरना होगा यादि अच्छा परिणाम चाहिए ।